

उनकी अनुपस्थिति में, यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि एक अपील, जो हमारे देश के प्रक्रियात्मक कानून में मूल मामले की दोबारा सुनवाई है, योग्यता के आधार पर उनके द्वारा दायर नहीं की जा सकती है। जहां तक याचिकाकर्ता नंबर 2 की अपील पर विचार करने से इनकार करने वाले आक्षेपित आदेश का सवाल है, हमें इसमें कोई दोष नहीं लगता है। निरस्तीकरण आदेश की वैधता के बारे में याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में सीधे चुनौती देना हमें प्रभावित नहीं करता है क्योंकि नियमित जांच के बाद निलंबन का आदेश निरस्त किया गया था, न कि अंतरिम चरण में। यदि शिकायतकर्ता को गुण-दोष के आधार पर अपील में सुनवाई का अधिकार नहीं है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इन कार्यवाहियों में उसे ऐसा अधिकार कैसे मिल सकता है। जैसा कि हमें प्रतीत होता है, याचिकाकर्ता इस मामले में शिकायतकर्ता होने के नाते अपनी कार्यवाहक सरपंच पद को बरकरार रखने के लिए अधिक उत्सुक है।

(7) उपरोक्त कारणों से, हम याचिका को तत्काल खारिज करते हैं।

आर.एन.आर

के.पी. भंडारी, के समक्ष

अपीलकर्ता।

प्रतिवादी।

न्यायामूर्ति जे .वी. गुप्ता और

राम दयाल (मृत) और अन्य, -

बनाम

हरियाणा राज्य,-

1976 का आर.एफ.ए. नंबर 389।

17 नवंबर, 1989

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) – धारा 149, 151 और 153। आदेश 6, नियम 17, आदेश 41, नियम – 3 और 22 – बढ़े हुए मुआवजे के लिए दावा – अपील के ज्ञापन में संशोधन के लिए आवेदन निर्णय के 10 साल बाद दायर किया गया। नियमित प्रथम अपील-आवेदन पोषणीय नहीं है।

यह माना गया कि आवेदन 10 वर्ष से अधिक समय के बाद दायर किया गया है? इस न्यायालय में अपील के निर्णय के बारे में। उक्त मामला पार्टियों के बीच अंतिम हो गया है और इसलिए, अपीलकर्ताओं को मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का दावा करने के लिए अपील के ज्ञापन में संशोधन करने की अनुमति देकर दस साल से अधिक समय के बाद इसे दोबारा नहीं खोला जा सकता है। एक बार अपील का निपटान हो जाने के बाद, वह अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है और इसलिए, दावेदारों के लिए आधार में संशोधन के लिए पूछना संभव नहीं था ताकि अपील के निपटान के लिए दावा बढ़ाया जा सके।

(पैरा- 2)

माना जाता है कि हमारी सुविचारित राय है कि राम बनाम हरियाणा राज्य, 1988 पीएलजे 505 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने बंता सिंह बनाम भारत संघ, आई.एल.आर. मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को खारिज नहीं किया है। (1988)2 पंजाब और हरियाणा 377.

(पैरा-3)

माना गया, आवेदन विचारणीय नहीं है और वह भी दस साल के बाद, इसलिए इसे तत्काल खारिज किया जा सकता है।

(पैरा-7)

आदेश 6, नियम 17 के साथ पठित आदेश 41, नियम 3 और 22 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 149, 151 और 153 के तहत प्रार्थना करते हुए कि यह आवेदन स्वीकार किया जाए, अपीलकर्ता याचिकाकर्ताओं को दावा करने के लिए अपील के ज्ञापन में संशोधन करने की अनुमति दी जाए। रु. मुआवजे की बढ़ी हुई राशि 2,50,000 रुपये के बजाय 2,50,000 रुपये होगी। 1,00,000 और अपीलकर्ता-याचिकाकर्ताओं को अदालत शुल्क की अतिरिक्त राशि रुपये का भुगतान करने की भी अनुमति दी जाए। 1464-00 और इस माननीय न्यायालय के 27 अप्रैल, 1979 के फैसले को कृपया दोबारा बुलाया जाए और संशोधित किया जाए ताकि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ताओं को रुपये की दर से अपीलकर्ता याचिकाकर्ताओं को देय मुआवजे की वास्तविक राशि मिल सके। 2,50,000 रुपये की राशि पर वैधानिक दरों पर 10 रुपये प्रति वर्ग गज की छूट और ब्याज के साथ।

एम. एस. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सरिता गुप्ता के साथ। याचिकाकर्ता के लिए वकील।

निमो, उत्तरदाताओं के लिए

निर्णय

माननीय जे.वी गुप्ता, जे

- (1) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से उत्पन्न 1976 की नियमित प्रथम अपील संख्या 389 पर इस न्यायालय द्वारा 27 अप्रैल, 1979 को निर्णय लिया गया था। अब, सी.एम. रुपये का दावा करने के लिए अपील के ज्ञापन में संशोधन की अनुमति के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा 1989 की संख्या 1762-सीआई दायर की गई है। मुआवजे की बढ़ी हुई राशि 2,50,000 रुपये के बजाय 2,50,000 रुपये होगी। 1,00,000. उन्होंने यह भी प्रार्थना की है कि उन्हें अदालती शुल्क की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जाए और तदनुसार, 27 अप्रैल, 1979 के फैसले को वापस लिया जाए और अपीलकर्ताओं को उन्हें देय मुआवजे की वास्तविक राशि प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए संशोधित किया जाए।
- (2) माना जाता है कि, इस न्यायालय द्वारा अपील के निर्णय के 10 वर्ष से अधिक समय के बाद आवेदन दायर किया गया है। उक्त मामला पार्टियों के बीच अंतिम हो गया है और इसलिए, अपीलकर्ताओं को मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का दावा करने के लिए अपील के ज्ञापन में संशोधन करने की अनुमति देकर दस साल से अधिक समय के बाद इसे दोबारा नहीं खोला जा सकता है। कैसे, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने नंद राम बनाम हरियाणा राज्य (1) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि इस तरह की राहत इस न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। उन्होंने सी.एम. में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का भी हवाला दिया। क्रमांक 1740-सीआई ऑफ 1985 (2), जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले पर भरोसा करते हुए आवेदन की अनुमति दी गई थी। इससे पहले, बंता सिंह बनाम भारत संघ (3) में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना था कि अपील लंबित होने पर अपीलीय अदालत अपीलकर्ता को निचली अदालत में और अपील में भी मांगी गई राहत में संशोधन करने की अनुमति दे सकती है। एक बार अपील का निपटारा हो जाने के बाद अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है और इसलिए, दावेदारों के लिए आधार में संशोधन के लिए पूछना संभव नहीं था ताकि अपील के निपटान के लिए दावा बढ़ाया जा सके। विद्वान वकील के अनुसार, नंद राम के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के बाद के फैसले के मद्देनजर, बंता सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ का फैसला, अब एक अच्छा कानून नहीं है।

- (3) विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारी सुविचारित राय है कि यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने किसी भी तरह से इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को खारिज कर दिया है।
- (4) सर्वोच्च न्यायालय ने नंद राम के मामले (सुप्रा) में विशेष अनुमति देते हुए अपील की अनुमति दी और उसमें कुछ राहत दी, जबकि यह न्यायालय इस स्तर पर अपील में नहीं बैठ रहा है और इसलिए, दावे के अनुसार कोई राहत देने का सवाल ही नहीं उठता है। . इसके अलावा, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में, इस पहलू पर विचार किया गया और यह देखा गया कि

“जैसा कि हमने पहले ही बताया है, अगर हम डिवीजन बेंच के फैसले पर अपील में बैठे हैं, तो हम ऊपर उल्लिखित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कर सकते हैं और आधारों में संशोधन की अनुमति देकर और डिक्री को संशोधित करके प्रार्थना की गई राहत प्रदान कर सकते हैं। बेंच और कोर्ट फीस के भुगतान के अधीन बढ़ा हुआ मुआवजा दे रही है। न तो हमारे सामने बेंच के फैसले के खिलाफ कोई अपील संभव है, न ही जैसा कि पहले ही कहा गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के तहत एक समीक्षा आवेदन संभव है।

इसे लिपिकीय या अंकगणितीय गलती भी नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्वान न्यायाधीशों ने निश्चित रूप से कहा कि उनकी राहतें अपील में दावों के संदर्भ में होंगी और यह अपील में उन्होंने जो मांगा है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। यदि आवेदक उस निर्देश से व्यथित थे, तो उन्हें अपील करनी चाहिए थी जैसा कि एआईआर 1985 एस.सी. 1576 (1985 पीएलजे 496) में रिपोर्ट किए गए निर्णय में किया गया है।

इसलिए, हम इस बात पर सहमत होने में असमर्थ हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं और इस मामले में राहत दे सकते हैं।”

- (5) जहां तक एकल पीठ के फैसले का संबंध है, संशोधित अधिनियम के तहत लाभ का दावा किया जा रहा था और इसका वर्तमान मामले के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है जहां 10 साल के बाद अपील के ज्ञापन में संशोधन की मांग की गई है। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, राज्य ने कभी भी आवेदन का विरोध नहीं किया, क्योंकि यह देखा गया कि, “आवेदन का गंभीरता से विरोध नहीं किया जा रहा है।” किसी भी मामले में, यह कहना गलत था कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसले ने पूर्ण पीठ के फैसले को खारिज कर दिया, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने देखा था।
- (6) सी.एम. में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है। आर.एफ.ए. में 1987 की संख्या 2001-सीआई. 1981 का क्रमांक 2671, 19 सितंबर 1988 को

निर्णय दिया गया, जिसमें इसी तरह के मामले पर विचार किया गया और बंता सिंह के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया।

(7) किसी भी कोण से देखने पर, आवेदन विचारणीय नहीं है और वह भी दस साल के बाद, इसलिए इसे तत्काल खारिज किया जा सकता है।

आर.एन.आर

पूरी

बेंच

न्यायामूर्ति जे. वी. गुप्ता, सी.जे.,

एम. एस. लिब्रहान और आर. एस. मोंगिया, जे.जे. के समक्ष

कंवलजीत

सिंह, -याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ, -प्रतिवादी।

1989 की सिविल रिट

याचिका संख्या 2886।

10 सितंबर

1990

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 356-पंजाब में आपातकाल की स्थिति-राष्ट्रपति शासन लागू करना-64वां संशोधन-संशोधन संविधान के अंतर्गत है-संशोधन बुनियादी ढांचे और लोकतंत्र का उल्लंघन नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरुग्राम, हरियाणा